न्यूज ब्रीफ

इमरान खान के बेहद करीबी उस्मान बुजदार ने छोड़ी राजनीति

क्वेटा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम व पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान के बेहद करीबी माने जाने वाले पाकिस्तान पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, क्वेटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उस्मान ने कहा कि वह पिछले 14 महीनों से कई केस का सामना कर रहे हैं। मैं राजनीति को छोड़ रहा हूं। बुजदार ने कहा कि ऐसा कोई नागरिक नहीं होगा जो 9 मई की इन घटनाओं की निंदा न करे। बुजदार ने कहा, मैं सेना के साथ खड़ा हूं और भविष्य में भी खड़ा रहूंगा। मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। इसके अलावा उन्होंने अपने संबोधन में कहा, निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ नरमी बरती जानी चाहिए और उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बुजदार ने कहा कि मैंने अच्छे इरादों के साथ लोगों की सेवा की है और मैं पिछले 14 महीनों से राजनीति में सक्रिय नहीं हूं। मीडिया के मुताबिक, बुजदार ने कहा कि वह हमेशा पाकिस्तान की सशस्त्र सेना के साथ खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। कभी इमरान खान के करीबी माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, मैं हमेशा अच्छी राजनीति के लिए प्रतिबद्ध रहा हूं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों के कारण मैंने राजनीति छोड़ने का फैसला किया है।

अमेरिका में फंगल इन्फेक्शन से 2 की मौत, कई जाने आफत में

वाशिंगटन। अमेरिका में फंगल इन्फेक्शन से 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों की जान आफत में पड गई है। मेक्सिको में कॉस्मेटिक सर्जरी कराना लोगों को खासा भारी पड़ रहा है। उनमें फंगल इंफेक्शन की शिकायतें देखने को मिली हैं। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया है कि मैक्सिकन शहर मैटामोरोस में एपिडयूरल एनेस्थेसिया से जुड़ी सर्जरी कराने वाले दो लोगों की मेनिन्जाइटिस से मौत हो गई है। इन दोनों लोगों ने लाइपोसक्शन कराया था, जिसमें शरीर के हिस्सों में जमी चर्बी हटा दी जाती है। इसके साथ ही अमेरिका और मैक्सिको में करीब 400 लोगों पर नजर रखी जा रही है। वहीं मैटामोरोस शहर में दो कॉस्मेटिक क्लीनिक बंद कर दिए गए हैं। कई अमेरिकी नागरिक लाइपोसक्शन, स्तन वृद्धि और ब्राजीलियन बट लिफ्ट जैसी कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए मेक्सिको जाते हैं। इस दौरान सभी को रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में सुन्न करने का एनेस्थीसिया दिया जाता है। सीडीसी के डलास स्मिथ ने बताया कि मैटामोरोस शहर में दो कॉस्मेटिक क्लीनिक में एनेस्थीसिया के दौरान उपयोग की जाने वाली दवाएं दूषित हो गई थी, जो मौजूदा प्रकोप की वजह है। सीडीसी ने लिखा, 'अधिकारियों ने प्रकोप से जुड़े दो क्लीनिकों की पहचान की है, रिवर साइड सर्जिकल सेंटर और विलनिका के-3 नामक ये क्लीनिक 13 मई, 2023 को बंद कर दिए गए थे।'सीडीसी ने चेतावनी दी है कि सैकड़ों और लोगों को खतरा हो सकता है। सीडीसी ने कहा कि उसने पहले ही अमेरिका में फंगल मैनिंजाइटिस के 'संदिग्ध' या 'संभावित' मामलों वाले 25 लोगों की पहचान कर ली है। जनवरी से लेकर 13 मई के बीच मैटामोरोस के क्लीनिकों की यात्रा करने वाले 200 से अधिक अमेरिकियों को खतरा है। मैनिंजाइटिस के लक्षणों में बुखार आना, सिरदर्द होना, गर्दन में अकड़न, उल्टी, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता और मानसिक स्थिति में बदलाव शामिल हो सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना पर शोक जताया

जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के अध्यक्ष चाबा कोरोशी ने ओडिशा में हुए भीषण ट्रेन हादसे को लेकर पीड़ित परिवारों के प्रति शोक जताया है। इस हादसे में 233 से ज्यादा यात्रियों के मारे जाने और 900 से अधिक यात्रियों के घायल होने की खबर है। शुक्रवार का हादसा भारत में हुई अब तक की सबसे भीषण रेल दुर्घटनाओं में से एक है, जिसमें ओडिशा के बालासोर जिले में तीन ट्रेन एक के बाद एक भयावह तरीके से एक-दूसरे से टकरा गईं। हादसे के बाद बालासोर में व्यापक राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया है। संरा महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कोरोशी ने ट्वीट किया ?कि भारत के ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों, उनके परिवारों और आपातकालीन सेवाओं के साथ हैं। यह ट्रेन दुर्घटना कोलकाता से 250 किलोमीटर दक्षिण और भुवनेश्वर से 170 किलोमीटर उत्तर में बालासोर जिले के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम लगभग सात बजे हुई। रेल मंत्रालय ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं।

एलन मस्क की चीन यात्रा से पश्चिमी देशों के 'एजेंडे' को झटका

बीजिंग।

जिस समय अमेरिका और यूरोप में चीन से संबंध-विच्छेद (डी-कपल) या संबंधों में जोखिम घटाने (डी-रिस्किंग) की चर्चा जोरों पर है, टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने एक अलग ही रास्ता अख्तियार कर लिया है। मस्क इस हफ्ते चीन की यात्रा पर आए। यहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। उधर मस्क ने यह साफ कर दिया कि वे चीन के साथ अपने कारोबारी रिश्तों को और मजबूत करेंगे।

एलन मस्क तीन साल के बाद चीन यात्रा पर आए। चीनी मीडिया में उनकी इस यात्रा को चीन की एक जीत रूप में पेश किया जा रहा है। कहा गया है कि मस्क ने यह साफ कर दिया है कि पश्चिम में हर कोई चीन से संबंध तोड़ने के बारे में नहीं सोच रहा है। इसके अलावा मस्क ने यह संकेत देने में भी कोई कोताही नहीं बरती कि एशिया अब इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और आविष्कार का नया केंद्र बन गया है। टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी रही है।

चीन सरकार मस्क और पश्चिम के दूसरे कारोबारियों की चीन यात्रा को हाई प्रोफाइल बनाने (बहुप्रचारित करने) में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मस्क से पहले अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन चेज के प्रमुख जेमी डिमॉन की यात्रा के समय भी ये बात सामने आई थी। विश्लेषकों के मुताबिक यह रुख अपना कर चीन यह संदेश देना चाह रहा है कि उसने व्यापार के लिए अपने दरवाजे फिर से खोल दिए हैं। इस तरह 2020 से अलीबाबा कंपनी के सीईओ जैक मा और

अन्य कंपनियों पर हुई कार्रवाई से बनी इस धारणा को वह तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि विदेशी पूंजी से अब चीन की दुश्मनी हो गई है।

अर्थशास्त्रियों के मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था इस समय संकटग्रस्त है। मई के आर्थिक आंकड़े और भी ज्यादा निराशाजनक रहे हैं। मई में चीन के मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ी गिरावट दर्ज हुई। यह लगातार तीसरा महीना रहा, जब ऐसी गिरावट दर्ज हुई। आर्थिक विश्लेषक केल्विन वॉन्ग ने वेबसाइट एशिया टाइम्स से कहा- चीन में मुद्रा संकुचन का खतरा है। इसके बीच चीन को गुजरे वर्षों में बनी धारणा को तोड़ना जरूरी हो गया है।

जापानी वित्तीय कंपनी नोमुरा इंटरनेशनल से जुड़े अर्थशास्त्री लू तिंग मैनुफैक्चरिंग पीएमआई में भारी गिरावट इस बात का संकेत है कि मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में मंदी की आशंका ठोस रूप लेती जा रही है। अमेरिकी बैंक गोल्डमैन सैक्श के अर्थशास्त्री हुई शान ने कहा है कि देश और विदेश दोनों जगहों पर मांग घटने के कारण चीन की आर्थिक वृद्धि दर अपनी गति खो रही है।

विशेषज्ञों के मुताबिक इन परिस्थितियों में चीन सरकार उसकी नीतियों को लेकर बनी धारणा को तुरंत बदलना चाहती है। इसीलिए एलन मस्क की यात्रा को प्रचारित करने में पूरा जोर लगाया गया है। मस्क के चीन से पुराने कारोबारी संबंध रहे हैं। उनकी कंपनी टेस्ला का शंघाई में एक बड़ा कारखाना है, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों का दुनिया भर में निर्यात होता है। ऐसे में चीन को खुश रखना उनकी जरूरत भी रही है। लेकिन यह माना जा रहा है कि जिस मौके पर पश्चिमी कंपनियां चीन से हटने के संकेत दे रही हैं, मस्क ने संबंध और बढ़ाने की बात कह कर पश्चिमी एजेंडे को चोट पहुंचाई है।

श्रीलंका में निकाय चुनाव टलने से बन रही विस्फोटक स्थिति

सरकार-विपक्ष के बीच टकराव बढ़ा, विक्रम सिंघे पर लगा तानाशाह बनने का आरोप

कोलंबो।

श्रीलंका में स्थानीय चुनावों को लगातार टालने के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघ सरकार के रुख के कारण विपक्ष के साथ उसका टकराव बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दल अब खुल कर राष्ट्रपति पर तानाशाही कायम करने के इल्जाम लगाने लगे हैं। प्रमुख विपक्षी दल समगई जना बलावेगया (एसजेबी) ने तो विक्रमसिंघे पर उगांडा के पूर्व तानाशाह इदी अमीन के नक्शे-कदम पर चलने का आरोप लगाया है। इदी अमीन 1970 के दशक में उगांडा के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने अपने विरोधियों का बेरहमी से दमन किया था।

एसजेबी के सांसद हर्षा राजकरुणा ने शुक्रवार को पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों और प्रांतीय परिषदों के लिए चुनाव पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली गई है और सारे देश को तानाशाही से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा- 'प्रांतीय परिषदों के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। अब तो इनकी चर्चा तक नहीं की जा रही है। प्रांतों को चलाने के लिए केंद्र सरकार ने अपने खास लोगों को गवर्नर बना दिया है। वही एक व्यक्ति सारे प्रांत को चलाता है।' राजकरुणा ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस मामले में कोर्ट के फैसले की भी अनदेखी कर दी है।

इस बीच यूनाइटेड नेशनल फ्रीडम एलायंस (यूपीएफए) ने कहा है कि अगर राष्ट्रपति विक्रमसिंघे सचमुच देश

में आम सहमति कायम करना चाहते हैं, तो उन्हें तुरंत राष्ट्रीय सरकार का गठन करना चाहिए। यूएनएफए के महासचिव तिलंगा समुथिपला ने कहा है कि अगर विक्रमसिंघे को सत्ता का मोह नहीं है, तो महत्त्वपूर्ण मसलों पर अन्य दलों का समर्थन हासिल कर सकते हैं। मौजूदा स्थिति में राष्ट्रीय सरकार के प्रस्ताव का विरोध कोई दल नहीं करेगा। लेकिन जिन मसलों पर आम सहमति नहीं बनेगी, उनका विरोध किया जाएगा।

यूपीएफ मोटे तौर पर पूर्व राष्ट्रपति मैत्रिपला सिरिसेना की पार्टी है। इस सदी के पहले दशक में वह सत्ता में थी। लेकिन बाद में इस पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता इससे अलग हो गए और उन्होंने श्रीलंका पोडुजना पेरामुना (एसएलपीपी) की स्थापना की, जो पिछले चुनाव में सत्ता में आई थी। विक्रमसिंघे एलएसपीपी के समर्थन से ही राष्ट्रपति बने थे। विक्रमसिंघे जुलाई 2022 में राष्ट्रपति बने थे। तब से वे देश में अहम मुद्दों पर आम सहमति बनाने की अपील करते रहे हैं।

स्थानीय और प्रांतीय चुनावों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के निजीकरण का मामला भी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव का मुद्दा बन गया है। एसजेबी ने शिकायत की है कि निजीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। इसमें टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि आर्थिक सुधार लागू करने और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के पुनर्गठन के नाम पर परदे की आड़ में डील किए जा रहे हैं।

हर्षा राजकरुणा ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि कोलंबो पोर्ट में 14 एकड़ जमीन एक चीनी कंपनी बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के दे दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने यह भी पहले से ही फैसला कर लिया है कि श्रीलंका टेलीकॉम और श्रीलंका इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को किसी निजी कंपनी को सौंपा जाएगा।

चीन ब्रिक्स करेंसी को आगे बढ़ाएगा या अपनी मुद्रा को?

केपटाउन।

ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) विदेश मंत्रियों की यहां हुई बैठक में इस समूह की अपनी साझा मुद्रा विकसित करना एक प्रमुख एजेंडा रहा है। इस बार इस बैठक को दो कारणों से खास तव्वजो रही है। उनमें एक है ब्रिक्स करेंसी के विकास की चर्चा और दूसरी वजह ब्रिक्स में नए देशों को शामिल करने का प्रस्ताव।

ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के साथ ही यहां फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें ब्रिक्स देशों के अलावा 15 अन्य देशों के विदेश मंत्री आए। पर्यवेक्षकों के मुताबिक मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने इन देशों के विदेश मंत्रियों को आमंत्रित कर एक तरह से ब्रिक्स के विस्तार की शुरुआत कर दी है।

इस बीच प्रस्तावित ब्रिक्स करेंसी को लेकर कई हलकों से यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इस प्रयास में चीन सचमुच शामिल होगा। विश्लेषकों के मुताबिक जिस समय चीन की अपनी मुद्रा युवान की अंतरराष्ट्रीय पैठ बढ़ रही है, संभव है कि किसी बहुराष्ट्रीय मुद्रा को आगे बढ़ाने में उसकी रुचि ना हो। ब्रिक्स बैठक से ठीक पहले अमेरिका की लॉयला यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड में एसोसिएट प्रोफेसर और वित्तीय मामलों के जानकार तुगी चुलउन के एक विशेष लेख ने इस चर्चा को बल दिया है।

चुलउन ने लिखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश होने के कारण चीन की मुद्रा को अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति मिल रही है। सबसे बड़ा निर्यातक होने के अलावा चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। चीन की इस हैसियत के बावजूद युवान को दुनिया की बड़ी मुद्राओं में नहीं गिना जाता था। लेकिन पिछले साल यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से सूरत बदल गई है। अब अंतरराष्ट्रीय कारोबार में युवान का इस्तेमाल करने वाले देशों की संख्या बढ़ रही है।

चुलउन ने लिखा है- 'वित्त का प्रोफेसर होने और अंतरराष्ट्रीय वित्त का विशेषज्ञ होने के नाते मैं यह समझ पा रहा हूं कि भू-राजनीतिक संघर्ष अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बनने की राह में चीन की मुद्रा को कैसे अगले चरण तक ले जा सकता है। और साथ ही इसे भी समझ पा रहा हूं कि इस परिस्थिति के कारण कैसे अमेरिकी मुद्रा डॉलर के वर्तमान वर्चस्व का क्षय शुरू हो सकता है।'

'युद्ध के हालात ना बनें, इसके लिए चीन से बातचीत जरूरी'

वॉशिंगटन

सिंगापुर में बीती रात शंगरी-ला डायलॉग डिफेंस समिट हुआ, जिसमें अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू भी शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने हाथ मिलाए लेकिन अमेरिका इससे संतुष्ट नहीं है। दरअसल शंगरी ला डायलॉग से इतर दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत होनी थी लेकिन बीते दिनों चीन ने अमेरिका की इस पेशकश को खारिज कर दिया था।

चीन द्वारा बातचीत की पेशकश खारिज होने पर अमेरिका ने निराशा जाहिर की है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि 'अमेरिका का मानना है कि चीन के साथ बातचीत के रास्ते खुले रहने चाहिए। खासकर हमारे रक्षा और सैन्य नेताओं के बीच बातचीत जरूरी है। जितना ज्यादा हम बातचीत करेंगे, उतनी ही गलतफहमी की आशंका कम होगी। इससे संघर्ष जैसे हालात नहीं बनेंगे।'

उल्लेखनीय है कि चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू को अमेरिका ने साल 2018 में प्रतिबंधित कर दिया था। दरअसल रूसी हथियार खरीदने के चलते ली शांगफू पर यह कार्रवाई की गई थी। माना जा रहा है कि चीनी रक्षा मंत्री के अमेरिका रक्षा मंत्री से बातचीत को खारिज करने की ये भी एक वजह है। हालांकि पेंटागन ने कहा कि प्रतिबंध के चलते आधिकारिक बातचीत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा कि वह चीन द्वारा बातचीत को लेकर अनिच्छा जाहिर करने से बेहद चिंतित हैं। अंतरराष्ट्रीय एयरस्पेस में अमेरिका और सहयोगी देशों के साथ हो रहे खतरनाक इंटरसेप्ट पर भी लॉयड ऑस्टिन ने चिंता जाहिर की। बता दें कि हाल ही में दक्षिण चीन सागर के ऊपर एयरस्पेस में अमेरिका और चीन के लड़ाकू विमान काफी नजदीक आ गए थे। ताइवान और चाइनीज जासूसी गुब्बारे के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के रिश्तों में कड़ावहट बढ़ी है। बता दें कि अमेरिका रक्षा मंत्री इन दिनों एशिया के दौरे पर आए हुए हैं।

अमेरिका दौरे पर नेल्सन मंडेला की बराबरी कर लेंगे पीएम मोदी, इस मामले में वाजपेयी से निकलेंगे आगे

वॉशिंगटन।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। बता दें कि पीएम मोदी अपने दौरे पर अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित भी करेंगे। ऐसा करते ही वह महान नेता नेल्सन मंडेला की बराबरी कर लेंगे। वहीं पीएम मोदी के अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने को लेकर इंडिया कॉकस के सांसद काफी खुश हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद और इंडिया कॉकस के सह-अध्यक्ष रो खन्ना ने बताया कि इंडिया कॉकस ने ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सभापति केविन मैक्कार्थी से अपील की थी कि वह पीएम मोदी को सदन के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करें।

नेल्सन मंडेला की बराबरी कर लेंगे पीएम मोदी - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 8 जून 2016 को भी अपने अमेरिका दौरे पर अमेरिकी सदन के संयुक्त सत्र को संबोधित कर चुके हैं। अब वह 22 जून को अपने आगामी दौरे पर दूसरी बार अमेरिकी सदन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी उन कुछ चुनिंदा महान नेताओं

की बराबरी कर लेंगे, जो दो या दो से ज्यादा बार अमेरिकी संसद को संबोधित कर चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले महान नेता नेल्सन मंडेला और इस्त्राइल के पूर्व पीएम यित्झाक राबिन भी दो बार अमेरिकी संसद को संबोधित कर चुके हैं। वहीं विस्टन चर्चिल और इस्त्राइल के मौजूदा पीएम बेंजामिन नेतान्याहु तीन-तीन बार अमेरिकी सदन को संबोधित कर चुके हैं।

राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी से आगे निकले - इस मामले में पीएम मोदी अपने पूर्ववर्ती राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव से अपने आगामी अमेरिका दौरे में आगे निकल जाएंगे। ये नेता एक-एक बार अमेरिकी सदन के संयुक्त सत्र को संबोधित कर चुके हैं। राजीव गांधी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 1985 में पहली बार अमेरिकी सदन को संबोधित किया था। अब अपने आगामी दौरे में पीएम मोदी दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे।

अमेरिकी सांसद उत्साहित - पीएम मोदी के सदन को संबोधित करने को लेकर अमेरिका का भारतीय मूल के सांसद और कई अन्य सांसद काफी उत्साहित हैं। पीएम मोदी को भेजे गए आमंत्रण पत्र में लिखा गया है कि अमेरिकी सदन के दोनों सदनों की तरफ से, यह हमारे लिए सम्मान की बात होगी कि आप 22 जून 2023 को सदन के संयुक्त सत्र को संबोधित करें। इस आमंत्रण पर केविन मैक्कार्थी, सीनेट के नेता चक शूमर, मिच मक्कॉनेल, हकीम जेफ्री के भी हस्ताक्षर हैं। पीएम मोदी के सदन को संबोधित करने को लेकर कई अमेरिकी सांसद उत्साहित हैं।

कंगाली के दौर में पहुंचा पाकिस्तान,

यूएई और सऊदी अरब ने भी हाथ खड़े किए

इस्लामाबाद।

पाकिस्तान इन दिनों बदहाली का शिकार हो रहा है। कर्ज का बोझ इतना है कि यूएई और सऊदी अरब ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। यहां बीते साल भर से राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक बदहाली जैसी डबल चुनौतियों से जूझ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप में खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तानी राजनीति में अस्थिरता भी चरम पर पहुंच गई। जिससे देश भर के प्रमुख शहरों में हिंसा भड़क गई। हंगामे ने खाड़ी में पाकिस्तान के सहयोगियों, विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और सऊदी अरब के बीच चिंता की लकीरें पैदा कर दी हैं। दोनों देशों ने पहले पाकिस्तान के लिए वित्तीय सहायता का वादा किया था। आंशिक रूप से पाकिस्तान में राजनीतिक अराजकता को बढ़ावा देना देश की गंभीर आर्थिक स्थिति है। मुद्रास्फीति हाल ही में 35.4 प्रतिशत के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। पिछले एक साल में ही पाकिस्तानी रुपये की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आधी हो गई है। सरकार के लिए शायद सबसे गंभीर बात यह है कि पाकिस्तान बाहरी कर्ज संकट का सामना कर रहा है।

जानकारी के अनुसार दिसंबर 2022 में इस्लामाबाद की बाहरी देनदारियां 126 बिलियन डॉलर से अधिक थीं। उच्च ब्याज दरों और मजबूत ग्रीनबैक के माहौल के बीच, ये डॉलर-मूल्यवान ऋण सेवा के लिए अधिक महंगे हो गए हैं। विशेष रूप से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के रूप में -

स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिसंबर में घोषणा की कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार चार साल के निचले स्तर 6.7 बिलियन डॉलर तक गिर गया है। इस बात की चिंता बढ़ रही है कि इस्लामाबाद अपने ऋणों पर चूक करेगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) डिफॉल्ट से बचने के लिए बेलआउट पैकेज को लेकर पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है। 2019 में पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ 6 बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके एक साल बाद 1 बिलियन डॉलर के समझौते पर सहमति बनी। कराची में एक ब्रोकरेज हाउस, टॉपलाइन सिक्योरिटीज के सीईओ मोहम्मद सोहेल ने बताया कि इस तरह की मांग प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन इस बात पर संदेह है कि क्या यूएई और अन्य सहयोगी बढ़ते राजनीतिक संकट को देखते हुए आगे धन की पेशकश करने के लिए तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि चीन, यूएई और सऊदी अरब पहले ही आईएमएफ को प्रतिबद्धता प्रदान कर चुके हैं। हालांकि, करीब 2 अरब डॉलर की प्रतिबद्धताएं अभी भी लंबित हैं। वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता के बीच यूएई और सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देता है, तो यह जोखिमों से भरा होगा। दोनों देशों के पाकिस्तान के साथ मजबूत व्यावसायिक रिश्ते हैं। लगभग 20 करोड़ से अधिक आबादी वाला पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई दोनों देशों के लिए एक बड़ा बाजार है। पाकिस्तान के आर्थिक संकट से पाकिस्तान-गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ट्रेड डील की व्यावहारिकता पर भी सवाल उठ सकते हैं।

अमेरिका में शाही परिवार की हवेली के पास दिखाई दिए एलियंस

न्यूयॉर्क। दुनिया के कई देशों में एलियंस के यान यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट (यूएफओ) देखने के दावे होते रहे हैं। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में किसानों ने भी कहा था कि एलियंस आते हैं और उनकी गायों के कान, नाक काटकर ले जाते हैं। एक पायलट ने भी आसमान में यूएफओ द्वारा पीछा करने की बात कही थी। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, इसकी तब जांच एक्सपर्ट कर रहे हैं। इसी बीच ब्रिटिश शाही परिवार के घर तक एलियन के पहुंचने की बात सामने आई है। अमेरिका में स्थित उनकी हवेली के बिल्कुल करीब एक गोलाकार चीज देखी गई है, जिसे एलियन का यान यानी उड़नतस्तरी बताया जा रहा है।